ओडीओपी के लिए हर जिले का बनेगा एक्शन प्लान

अमर उजाला ब्यूरो

प्रमुख सचिव ने 30 नवंबर तक जिलों से मांगी कार्ययोजना

जिलों में एसडीएम स्तर का अधिकारी होगा नोडल अफसर

लखनऊ। प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए हर जिले का एक्शन प्लान बनेगा। ओडीओपी योजना से जुड़े उद्यमियों की सुविधा के लिए जिलों में कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी बनेंगे। विभाग के प्रमुख सचिव नवनीत सहगल के निर्देश के बाद अब इसकी कार्ययोजना तैयार की जा रही है। सहगल ने 30 नवंबर तक जिलों को कार्य योजना भेजने के निर्देश दिए हैं।

जिले के उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए बनने वाले एक्शन प्लान में उद्यमियों को बैंकों से वित्तीय सहायता दिलाने में मदद करने, उन्हें अत्याधुनिक तकनीक की मशीनों व उपकरणों की जानकारी व प्रशिक्षण देने व कम लागत पर अच्छी डिजाइन के उत्पादन तैयार कर बाजार उपलब्ध कराने की योजना है। कार्य योजना को जल्द ही सीएम के सामने पेश किया जाएगा।

पहले चरण में 14 जिलों पर फोकस : ओडीओपी के पहले चरण में लखनऊ, आगरा, कानपुर, सहारनपुर, गोरखपुर, मुरादाबाद, सिद्धार्थनगर, अलीगढ़, आजमगढ़, बरेली, वाराणसी, भदोही, फिरोजाबाद और अंबेडकरनगर जैसे जिलों पर खास फोकस होगा। विभाग का मानना है कि इन जिलों में चिकन, लेदर, ताला, सिल्क, कालीन, कांच के सामान व चूड़ी उद्योगों की खास पहचान है।

सरकार की मंशा है कि एक से डेढ़ साल में ओडीओपी के नतीजे दिखने लगे। हर जिले की योजना बनाने से काम आसान होगा। - **नवनीत सहगल, प्रमुख सचिव एमएसएमई**

देश-विदेश के मेलों में जाएंगे उद्यमी

देश-विदेश में होने वाले मेलों और प्रदर्शनियों में भी ओडीओपी उद्यमियों को भेजा जाएगा। इसके लिए देश-विदेश में होने वाले प्रमुख मेलों की रिपोर्ट तैयार की गई है। पारंपरिक उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए भी सभी जिलों में भी मेले व प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। ओडीओपी योजना के संचालन के लिए हर जिले में एडीएम स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा।

Scanned by CamScanner